*Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*
*Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540*

# प्राथमिक स्तर पर सरकारी और निजी स्कूलों की स्थिति का अध्ययन

**Deepak Jain[1]*, Dr. Sandeep Kumar[2]**

[1] Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P. India

Email: deepakjain62193@gmail.com

[2] Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P. India

***सार -*** ***निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। इसका अर्थ न केवल शिक्षा या शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का लक्ष्य है बल्कि जीवन परीक्षा और सीखने के परिणामों की तैयारी भी है। जब छात्र अपने सीखने के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं तो सीखने के परिणाम महत्वपूर्ण या आनंददायक हो जाते हैं। आजकल निजी स्कूल उच्च शिक्षा में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र हैं और आंकड़े निजी क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र की गिरावट को दर्शाते हैं। भारत के निजी स्कूलों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। अध्ययन करने पर पता चलता है कि निजी स्कूलों शिक्षा की गुणवत्ता सरकारी स्कूलों से बेहतर है। अध्ययन का उद्देश्य इन मुद्दों पर चर्चा करना है प्राथमिक शिक्षा, पब्लिक और निजी प्राथमिक विद्यालय में तुलना, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक शिक्षा, वैदिक काल के दौरान प्रारंभिक शिक्षा, बौद्ध काल के दौरान प्रारंभिक शिक्षा, ब्रिटिश काल में प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षण और सीखने का वातावरण***

***खोजशब्द: शिक्षा, सरकारी, निजी***

----------X----------

**परिचय**

भारत का भाग्य इस समय उसके वर्ग में निर्मित हो रहा है। हम मानते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है। विज्ञान और शिल्प विज्ञान पर आधारित इस दुनिया में शिक्षा लोगों के सुख, कल्याण और सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करती है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों से बाहर आने वाले छात्रों की योग्यता राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की संस्था पर उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता पर निर्भर करेगी, जिसका मुख्य लक्ष्य हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में प्राथमिक स्तर का विशेष महत्व है। यही वह अवस्था है जब व्यक्तित्व के विकास की नींव रखी जाती है। इस अवस्था में बच्चे में डाले गए संस्कार उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। बच्चे को जितने विविध और समृद्ध अनुभव होंगे, विकास उतना ही प्रभावी होगा। इस अवस्था में बच्चों में रुझान, खोज, जिज्ञासा, विश्लेषण आदि का विकास होता है। हमारे देश में शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के तीन स्तरों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा हमारी शिक्षा का आधार है। इसी नींव पर शिक्षा की नींव पड़ती है।[1]

बुनियादी शिक्षा प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पहली अनिवार्यता का उद्देश्य है। यह पहली सीढ़ियाँ हैं जो किसी राष्ट्र के वांछित लक्ष्य को सफलतापूर्वक पार करके सफलतापूर्वक पहुँचती हैं। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ठ संबंध है, प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक और उच्च शिक्षा के समान नहीं है। प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय विचारधारा और चरित्र के योगदान का बहुत बड़ा योगदान है। प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि पूरी आबादी से होता है। हर कदम पर हर व्यक्ति के जीवन से उसका संपर्क है।

स्कूल एक ऐसा विशेष वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुण और कुछ प्रकार की गतिविधियों और व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बच्चे का विकास वांछित दिशा में हो। ये शिक्षण संस्थान मानव जीवन और मानव जीवन शिक्षा संस्थानों को प्रभावित करते हैं। शिक्षा

www.ignited.in

संस्थानों या स्कूलों का समाज और समाज पर स्कूलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, दोनों एक दूसरे की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। प्राथमिक शिक्षा बच्चों को पृथ्वी के प्रति बहुमुखी बनाती है, उनमें सामान्य परोपकारिता और सहयोग की भावना का निर्माण करती है। उसका शारीरिक और मानसिक विकास, भाषा, कला और संगीत आदि का विकास आत्म-क्षमता का विकास करके अभिव्यक्ति उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, उनमें नागरिकता देती है, गुणों का विकास करती है और उनमें नैतिकता की भावना पैदा करती है। कोठारी आयोग (1964-66) ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को भविष्य के जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाना है ताकि वह इस तरह से शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण प्रदान कर सके कि वह ऐसा कर सके यह वास्तव में एक उपयोगी नागरिक बन सकता है।[2]

तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की श्रेणी में भारत का विशेष स्थान है। हमारे देश की जरूरतों की जरूरतें, कई क्षेत्रों की प्रगति और उपलब्धियों का हमारे जीवन पर एक उन्मुखीकरण है; लेकिन दुनिया के कई देश भी हमें उम्मीद के मुताबिक देखते हैं। जैसा कि ज्ञात है, किसी भी देश की प्रगति का कारण उसके मूल निवासियों द्वारा अपने देश के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा दायित्वों की रिहाई में निहित है। दूसरी ओर, नैतिकता में सुधार, जीवन की गुणवत्ता और रहने की स्थिति का सीधा संबंध शिक्षित होने से है। निरक्षरता एक अभिशाप है जो भारत में मिट नहीं रहा है। इस निरक्षरता अभिशाप को कम करने के लिए हमारे देश और राज्य में सरकारी और गैर-सरकारी संगठन बनाए जा रहे हैं और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार और शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कई कदम उठा रहे हैं।[3]

**प्राथमिक शिक्षा**

मानव पूंजी के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है। देश की शिक्षा प्रणाली का उसकी मानव पूंजी की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत उत्पादकता और दक्षता को केवल शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, जो कि सतत आर्थिक विकास को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। व्यापक निरक्षरता से आर्थिक प्रगति बाधित है। अविकसित देशों में आर्थिक विकास और जीवन स्तर को बढ़ावा देने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक प्राथमिक शिक्षा है। हालाँकि, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, यदि प्रारंभिक शिक्षा को नई जानकारी और उचित तकनीकी कौशल से समृद्ध किया जाए। गरीबी के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना है। यह अनिवार्य शिक्षा का प्रारंभिक स्तर है, जो विद्यार्थियों की भविष्य की शैक्षणिक सफलता की नींव रखता है और कई लोगों द्वारा इसे एक बुनियादी मानव अधिकार माना जाता है। सार्वजनिक और निजी स्कूल दो मुख्य प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज की दुनिया में, प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा भयंकर है। दुनिया की शिक्षा प्रणाली का हर पहलू अपने विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रयासों की सफलता पर घूमता है। जब बच्चों की शिक्षा की बात आती है, तो माता-पिता उनके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। इन मांगों के कारण सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूल छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर हैं। जब इस लड़ाई की बात आती है, तो यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसका क्षेत्र सबसे प्रभावी और कुशल है।[4]

**पब्लिक और निजी प्राथमिक विद्यालय में तुलना**

सार्वजनिक बनाम निजी स्कूलों का तुलनात्मक अध्ययन और उनकी प्रभावशीलता बड़ी संख्या में अध्ययन का विषय रहा है। सार्वजनिक और निजी स्कूलों की विभिन्न विशेषताओं की तुलना करने के लिए दुनिया भर में कई अध्ययन किए गए हैं। शोधकर्ताओं ने प्रदर्शन के विभिन्न उपायों पर ध्यान केंद्रित करके दोनों में से किसी एक की श्रेष्ठता का बोध कराने की कोशिश की। नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस के अनुसार, जो विभिन्न विषय क्षेत्रों में अमेरिकी छात्रों के ज्ञान के आकलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि है, रिपोर्ट करता है कि निजी स्कूलों ने गणित और विज्ञान सहित सभी प्रमुख विषय क्षेत्रों में पब्लिक स्कूलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। गणित में अमेरिकी छात्रों की उपलब्धि के विश्लेषण के एक अन्य अध्ययन में, निजी स्कूलों ने अधिकांश मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि पब्लिक स्कूलों ने तथ्यों के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया। [5]

विकासशील देशों के गरीब क्षेत्रों में भी विकसित देशों में निजी स्कूलों का प्रदर्शन नहीं होता है। नाइजीरिया के लोगोस राज्य के एक गरीब इलाके में एक सर्वेक्षण किया गया और यह पाया गया कि निजी स्कूलों में 75% बच्चे नामांकित थे, जबकि निजी स्कूलों में शिक्षण गतिविधियाँ पब्लिक स्कूलों की तुलना में अधिक थीं। ज्यादातर विकासशील देशों में, सार्वजनिक क्षेत्र शिक्षा के प्रावधान के लिए मुख्य भूमिका निभाता है; यहां तक कि शिक्षा भी

www.ignited.in

बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत विशेषताओं और स्कूल की पसंद को नियंत्रित करके प्रभावशीलता के एक उपाय के रूप में श्रम बाजार की कमाई को लेकर सार्वजनिक बनाम निजी स्कूलों की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए इंडोनेशिया में एक अध्ययन आयोजित किया निष्कर्ष बताते हैं कि निजी स्कूल सार्वजनिक स्कूल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का एक फायदा है।[6]

**भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक शिक्षा**

1947 के बाद के समय को स्वतंत्र काल कहा जाता है। गुलामी के गुलामों को तोड़कर भारत ने 1947 में आजादी हासिल की और इसके बाद स्वतंत्र भारत की नई परिस्थितियों और स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए गए। स्वतंत्रता का दिन, यह भारतीय इतिहास में भारतीय लोगों के सबसे सुखद आंदोलन का गवाह और साझा करता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक तस्वीर बिल्कुल अलग थी। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर शिक्षा के हर क्षेत्र में शुरुआती संतुलन बेहद कम था और सभी पहलुओं में निराशाजनक था जैसे शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब, पुरुषों और महिलाओं के बीच शैक्षिक असमानता और असंतुलन बहुत बड़ा था। स्वतंत्रता के बाद भारत को शिक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है जो सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय उत्थान के लिए आवश्यक साधन है। शैक्षिक समस्याओं की समीक्षा करने और उन्हें बदलती जरूरतों, लोगों की आकांक्षाओं, संरचना और शिक्षा की रणनीति में समायोजित करने के लिए सुझाव देने के लिए कई समितियों और आयोगों की आवश्यकता थी। स्वतंत्र भारत न्याय, स्वतंत्रता और समानता देने के लिए प्रभावी संविधान चाहता है और भारत के लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना चाहता है।

भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के मद्देनजर सुचारु परिवर्तन के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में उठाया गया पहला कदम संविधान का अनुच्छेद 45 पेश किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत संविधान में राज्य की नीति के सिद्धांत के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जिसमें राज्यों को संविधान के लागू होने पर दस वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करना था। हालांकि यह लक्ष्य हाल ही में अप्रभावी था जब तक कि सरकार ने अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 नहीं दिया। [7]

साठ के दशक में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण, अध्ययन, समीक्षा और सुधार की सिफारिश करने के लिए आयोगों की एक श्रृंखला की नियुक्ति देखी गई। इन आयोगों की रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने शिक्षा प्रणाली में कुछ आवश्यक बदलाव लाने के लिए कदम उठाए। भारत में शिक्षा को राज्यों और केंद्र की संयुक्त जिम्मेदारी बना दिया गया है। केंद्र का प्रतिनिधित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों के साथ मिलकर करता है; यह शिक्षा नीति के निर्माण के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। [8]

**वैदिक काल के दौरान प्रारंभिक शिक्षा**

वैदिक काल वेदों की रचना और वेदों पर आधारित शिक्षा प्रणाली का युग है। इस काल के अंतिम वर्षों में वेदों के भाष्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आदि की रचना भी हुई। यदि हम वैदिक काल को देखें, तो हम पाएंगे कि भारत में सार्वभौमिक शिक्षा की अवधारणा कभी भी एक नया विचार नहीं है। यह उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता की शुरुआत। भारतीय शिक्षाविदों ने इस बात की वकालत की कि शिक्षा को न केवल कुछ इष्ट लोगों की, बल्कि पूरे समाज की जरूरतों और विकास को पूरा करना चाहिए। इस देश में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता के न्यूनतम मानक के साथ आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। गृह्य सूत्र में कहा गया है कि दो बार जन्म लेने वाली तीन जातियों को धार्मिक छात्रवृति के दौर से गुजरना पड़ता था। गृह सूत्र में कहा गया है कि दो बार जन्म लेने वाली तीन जातियों को आध्यात्मिक छात्रवृति के दौर से गुजरना पड़ा। राजा अर्वापति कैकेय ने छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि, "मेरे राज्य में कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं है" उपरोक्त कथन स्पष्ट करता है कि प्राचीन आर्यावर्त में एक सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा प्रणाली थी।

**बौद्ध काल के दौरान प्रारंभिक शिक्षा**

इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म का उदय हुआ और बौद्ध धर्म के अनुसार एक नई प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई। जातक कथाओं से हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्ध मठ शिक्षा के केंद्र थे। प्रारंभ में यह शिक्षा केवल धार्मिक थी, लेकिन कुछ समय बाद विश्व शिक्षा भी दी गई। कारण यह था

www.ignited.in

कि ब्राह्मणों द्वारा चलाई जा रही प्रतिद्वन्दी शिक्षण संस्थाओं में दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। ऐसे में यह आवश्यक था कि बौद्धों के लिए भी दोनों प्रकार की शिक्षा का आयोजन किया जाए। ऐसा करने से ब्राह्मणों के एकमात्र अधिकार को शिक्षा से समाप्त किया जा सकता था।

बौद्ध मठों में फाह्यान में भारत के आगमन के समय, बौद्ध संघ में शामिल होने वालों की शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा की एक बहुत अच्छी व्यवस्था भी थी। चीनी यात्रियों के लेखों में हमें सार्वजनिक या प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है - हुयानसांग और आइसिंग, जो 7 वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन यात्रियों के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा 7 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। छात्र छह महीने तक 'सिद्धिरस्तु' किताब पढ़ते थे, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर शामिल थे। इसे पूरा करने के बाद, छात्र शब्द-विद्या, शिल्प-विद्या, चिकित्सा-विद्या और आध्यात्म (आध्यात्मिक) विद्या का अध्ययन कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा का उपरोक्त विवरण स्पष्ट करता है कि बौद्ध मठों में धार्मिक, सांसारिक, दार्शनिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था।[9]

**ब्रिटिश काल में प्रारंभिक शिक्षा**

ब्रिटिश काल के दौरान, भारत का शासन काफी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज्य प्रणाली के अधिकार में रहा और इस समय अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी संस्कृति और विज्ञान पर आधारित था। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रारंभ में ईसाई मिशनरियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना और भारतीयों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। भारतीयों को भी इन स्कूलों में प्रवेश लेने की अनुमति थी। तीन प्रकार के विद्यालय अस्तित्व में आए। वे थे: मिशनरी स्कूल, वर्नाक्युलर स्कूल और सरकारी स्कूल। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा थी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1781 में कलकत्ता मदरसा के संस्थापक थे, जिन्होंने मुस्लिम अधिकारियों को कानून अदालतों में काम करने के लिए पेश किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये कॉलेज एक लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान की सहायता से जीवित रहे। भारतीय शिक्षा का विकास उस समय हुआ जब समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने 1816-1817 में कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की जो बाद में 1855 में प्रेसीडेंसी कॉलेज बन गया। कुछ अन्य विदेशों में प्रतिबद्ध ईसाई मिशनरियों ने भी पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में कॉलेज शुरू किए।

भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य घटना 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत थी। 1835 में, मैकाले के प्रसिद्ध मिनट ने देश में स्वदेशी शिक्षा को मौत का झटका दिया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। इसका खामियाजा देशी स्कूलों को भुगतना पड़ा। बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी ने प्राथमिक शिक्षा के समर्थन में उत्कृष्ट कार्य किया। सोसायटी ने पंद्रह प्राथमिक विद्यालय खोले। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य मातृभाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना था। 1840 में, बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी को बॉम्बे बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा बदल दिया गया था, जो 1855 तक कार्य करता था। [10]

**शिक्षण और सीखने का वातावरण**

शिक्षण और सीखने का वातावरण बच्चे के सीखने के लिए एक पूर्व शर्त है। बच्चे के लिए उपलब्ध उचित शिक्षण और सीखने का वातावरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के सीखने को प्रभावित करता है। यह भौतिक, शैक्षिक, सामाजिक वातावरण और सहायक सेवाओं से संबंधित है। शोधों ने संकेत दिया था कि छात्रों का प्रदर्शन हमेशा उच्च होता है जिसमें स्कूलों में उचित शिक्षण और सीखने का माहौल होता है। शिक्षण और सीखना प्रभावी सीखने की केंद्रीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकों और छात्रों को बातचीत के अवसर मिलते हैं, जिससे सीखने में सुविधा और वृद्धि होती है। छात्रों की प्रगति और कमजोरी को सुनिश्चित करने के लिए नियमित मूल्यांकन बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आम तौर पर सभी स्कूलों में, पाठ्यचर्या को संचालित करने के लिए पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र मुख्य उपलब्ध स्रोत/उपकरण होता है। मोटे तौर पर, शिक्षण अधिगम सामग्री में पूरक पठन सामग्री, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण सहायक सामग्री (श्रव्य, दृश्य और श्रव्य-दृश्य), कार्यपुस्तिकाएं, शिक्षक मार्गदर्शिका, गणित किट, विज्ञान किट, अंग्रेजी किट आदि शामिल हैं। शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना चाहिए। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया प्रभावी। छात्र मूल्यांकन शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और यह निरंतर और व्यापक होना चाहिए। यह शिक्षक को सीखने वाले छात्रों की प्रतिक्रिया भी देता है जिसके संबंध में शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों और शिक्षण शैली को संशोधित कर सकता है। यदि स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहता है, तो स्कूल को

www.ignited.in

छात्रों के व्यवस्थित और निरंतर और व्यापक मूल्यांकन को लागू करना चाहिए।[11]

**निष्कर्ष**

विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक और निजी स्कूल अलग-अलग तरीके और अलग-अलग तरीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, हालांकि पब्लिक स्कूल में अच्छे कर्मचारी हैं, फंड जो सरकार द्वारा प्रदान करते हैं लेकिन वे प्रौद्योगिकी, अध्ययन सामग्री, बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के पेशे के रवैये को अद्यतन नहीं करते हैं। तुलनात्मक रूप से निजी स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अधिक लाभकारी या लाभदायक हैं। वे उस तकनीक, अध्ययन सामग्री जैसी हर चीज को समय पर अपडेट कर रहे हैं। वे अपने प्रतिस्पर्धियों से प्रतियोगिता की योजना बनाते हैं और शिक्षकों को उनकी व्यावसायिक योग्यता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निजी स्कूलों में फीस सरकारी की तुलना में अधिक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में छात्र कम फीस के लिए सरकारी स्कूलों को पसंद करते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं और साथ ही शहरी क्षेत्र में छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी स्कूल पसंद करते हैं। हमारे अध्ययन के अनुसार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निजी स्कूलों की विकास दर लगातार बढ़ रही है और निजी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सरकारी स्कूल शिक्षा की तुलना में काफी बेहतर है।

**संदर्भ**

1. सिल्बरमैन, एम। (1996)। सक्रिय शिक्षण: किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए 101 रणनीतियाँ। अप्रेंटिस-हॉल, पीओ बॉक्स 11071, डेस मोइनेस, आईए 50336-1071।

2. स्टैंड्रिज, एम (2002)। व्यवहारवाद। मोरे (एड।) में, सीखने, शिक्षण और प्रौद्योगिकी पर उभरते दृष्टिकोण।

3. स्टीफन माइकल एट अल। (2007)। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण एविएशन सिक्योरिटी स्क्रीनर्स द्वारा एक्स-रे इमेज इंटरप्रिटेशन में दक्षता बढ़ाता है, सुरक्षा प्रौद्योगिकी पर 41 वां वार्षिक IEEE अंतर्राष्ट्रीय कार्नाहन सम्मेलन।

4. सिबिचेन, के.के. (2011)। माध्यमिक शिक्षक शिक्षा के छात्रों के तकनीकी_शैक्षणिक और सोच कौशल।

5. सत्यराज के और राजशेखर एस (2013)। उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की तकनीकी शैक्षणिक योग्यता और शिक्षण में निर्देशात्मक सहायता के उपयोग के प्रति उनकी चिंता के बीच संबंध। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशनल रिसर्च (IJTER) 2,12।

6. सेगेव, ई। (2014)। मोबाइल लर्निंग: कभी भी, कहीं भी अपनी अंग्रेजी सुधारें। ब्रिटिश काउंसिल.

7. सेज़र, बी। (2015)। कुछ चरों के संदर्भ में शिक्षकों की तकनीकी-शैक्षणिक ज्ञान दक्षताओं की जांच करना। प्रोसीडिया-सामाजिक और व्यवहार विज्ञान, 174, 208-215।

8. शेट्ज़, डी।, बशरौश, आर।, और वॉल, जे। (2017)। साइबर सुरक्षा की अधिक प्रतिनिधि परिभाषा की ओर। डिजिटल फोरेंसिक, सुरक्षा और कानून के जर्नल, 12(2), 8.

9. सौरैचे @वेंगुइदरगावने और सेलवन (2017)। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों, अप्रकाशित पीएच.डी शोध प्रबंध, अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी के बीच मुकाबला रणनीतियों पर ज्ञान विकसित करने में पूर्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा सिखाने के लिए पाठ्यचर्या दृष्टिकोण और तरीके।

10. सिवो, एस.ए., कू, सी.एच., और आचार्य, पी। (2018)। यह समझना कि संसाधनों के बारे में विश्वविद्यालय के छात्रों की धारणा ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रौद्योगिकी स्वीकृति को कैसे प्रभावित करती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के ऑस्ट्रेलियाई जर्नल, 34(4)।

**Corresponding Author**

**Deepak Jain***

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P. India

Email: deepakjain62193@gmail.com

www.ignited.in